भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2499
उत्तर देने की तारीख 21 दिसम्बर, 2022

दूरस्थ गांवों में मोबाइल टावर लगाना

2499. श्री आर. के. सिंह पटेल:
श्री भागीरथ चौधरी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के विभिन्न दूरस्थ गांवों में अभी भी मोबाइल टावर नहीं लगाए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो दूरस्थ गांवों में संचार क्रांति से जुड़ी इस परिकल्पना के कब तक साकार हो जाने की संभावना है;
(ग) क्या उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिले के विभिन्न गांवों तथा राजस्थान के कई जिलों के विभिन्न गांवों में बीएसएनएल मोबाइल टावर लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार चित्रकूट और बांदा में 5जी सेवाएं शुरू करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने राजस्थान में 4जी सेवाएं शुरू की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ख) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों और राज्य सरकारों से मार्च 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 6,44,131 गांवों में से (गाँवों की संख्या भारत के महापंजीयक के नवंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार हैं) देश में लगभग 6,05,230 गाँवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध है और 38,901 गाँवों में मोबाइल टावर और कवरेज नहीं है। सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) देश में चरणबद्ध तरीके से दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से वित्तपोषण के माध्यम से सरकार देश के सभी सेवा से वंचित गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। यूएसओएफ की प्रमुख स्कीमें इस प्रकार हैं:

- देश भर के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का सैचुरेशन। अनुमानित परियोजना लागत 26,316 करोड़ रूपये है।
- वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र चरण-II में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। अनुमानित परियोजना लागत 2211 करोड़ रूपये है।
- सभी वामपंथी उग्रवाद के चरण-I साइटों का 2जी से 4जी मोबाइल प्रौद्योगिकी में उन्नयन। अनुमानित परियोजना लागत 2425 करोड़ रूपये है।

- एनईआर के लिए व्यापक दूरसंचार विकास कार्यक्रम के तहत देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। अनुमानित परियोजना लागत 3637 करोड़ रूपये है।

- आकांक्षी 7,287 जिला गांवों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा) में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान और चार राज्यों (अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) के आकांक्षी जिलों के 502 सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 7152 करोड़ रूपये है।

- जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, सीमा क्षेत्र और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सेवा से वंचित 354 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 337 करोड़ रूपये है।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 85 सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान और एनएच223 का निर्बाध 4जी मोबाइल कवरेज। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 130 करोड़ रूपये है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट और बांदा जिलों के लिए बीएसएनएल के मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए जनता की इस प्रकार की कोई मांग लंबित नहीं है। चित्रकूट जिले के 657 गांवों में से 635 गांवों को मोबाइल नेटवर्क से कवर किया गया है और 22 गांव सेवा से वंचित हैं उन्हें भी यूएसओएफ स्कीम के तहत मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किया जा रहा है। बांदा जिले के सभी 734 गांवों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है। राजस्थान राज्य के 46,077 गांवों में से 42,761 गांवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध है और शेष गांवों को सरकार और टीएसपी द्वारा चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा रहा है।

(घ) स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए दिनांक 15-06-2022 के आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईए) और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार रोलआउट दायित्वों का स्पेक्ट्रम आवंटन की तारीख से पांच साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अनिवार्य रोलआउट दायित्वों से बाहर मोबाइल नेटवर्क के आगे का विस्तार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के तकनीकी-वाणिज्यिक विचार पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट और बांदा जिलों सहित देश में 5जी सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही हैं।

(ङ) से (च) राजस्थान राज्य में 4जी सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। 4जी सेवा युक्त गांवों का जिला-वार विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

अनुबंध-I

माननीय संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 21/12/2022 को "दूरस्थ गांवों में मोबाइल टावर लगाना" के संबंध में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2499 के भाग (ङ) से (च) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

राजस्थान राज्य में 4जी मोबाइल से कवर गांवों का जिले-वार विवरण नीचे दिया गया है:

मार्च'2022 तक राजस्थान में 4जी मोबाइल कवरेज की जिले-वार स्थिति			
क्रं. सं.	जिले का नाम*	आरजीआई डेटा के अनुसार गांवों की कुल संख्या (दिनांक 30-11-2019)	4जी मोबाइल कवरेज वाले गांवों की संख्या
1	अजमेर	1128	1098
2	अलवर	2067	1998
3	बांसवाड़ा	1540	1481
4	बारां	1233	1178
5	बाड़मेर	2964	2271
6	भरतपुर	1530	1521
7	भीलवाड़ा	1910	1831
8	बीकानेर	946	830
9	बूंदी	881	858
10	चितौड़गढ़	1771	1555
1 1	चुरू	904	892
12	दौसा	1136	1051
13	धौलपुर	834	781
14	डूंगरपुर	1014	961
15	गंगानगर	3024	2987
16	हनुमानगढ़	1909	1870
17	जयपुर	2264	2145
18	जैसलमेर	855	444
19	जालोर	822	796
20	झालावाड़	1626	1547
21	झुंझुनूं	982	873
22	जोधपुर	1909	1759
23	करौली	900	801
24	कोटा	879	876
25	नागौर	1641	1588
26	पाली	1047	945
27	प्रतापगढ़	1009	942
28	राजसमंद	1084	839
29	सवाई माधोपुर	825	797
30	सीकर	1191	1147
31	सिरोही	506	427
32	टोंक	1210	1185
33	उदयपुर	2536	2069
कुल		**46077**	**42343**

*जिले की संख्या भारत के महापंजीयक के नवंबर 2019 तक के आकड़ों के अनुसार हैं।

*****